कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गयी नयी किस्में को० जे० 64 और को० जे० 67 हैं। इनमें से को० जे० 64 अधिक चीनी वाली और जल्द तैयार होने वाली है जबकि को० जे० 67 किस्म मध्यम समय में तैयार होने वाली है।

(ग) जी हां, श्रीमान। पंजाब के अतिरिक्त को० जे० किस्म हरियाणा में भी रिलीज की गई है। गन्ने की अधिकांश उन्नत किस्मों का मूल क्रास संयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान में विकसित किया गया है—बाद में उन किस्मों से विभिन्न राज्यों में स्थित अनुसंधान केन्द्रों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों का विकास किया गया है। अन्य राज्यों में इस तरह की वितरित की गई उन्नत किस्में ये हैं :-को० 7314, को० 7321, को० 767, को० 770, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में; को० 6311, को० 7104, को 7114, असम में, को० पी० 1, को० पी०-2, पूर्वी क्षेत्र के लिए ; को० 7508, को० 7334, को० ए० 7701, को० ए० 7602, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती जिलों में और को० सी० 671, को० सी० 771, को० सी-772, को० सी० 776, को० 7704, को० 7219, को० एम० 7114, को० एम० 7125, को० आर० 8001, को० 6907, महाराष्ट्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का निर्यात

4620. **श्री निहाल सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1980 और 1981 के दौरान भारत के लिए निर्यात हेतु चीनी का कितना कोटा आबंटित किया गया है ;

(ख) क्या भारतीय प्राधिकारियों ने इस वर्ष और अधिक कोटा आवंटित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन को अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात प्रयोजन के लिए अन्य देशों के साथ किए गए अनुबन्धों का ब्योरा क्या है और ऐसे देशों के नाम क्या हैं और 1982 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की चीनी निर्यात की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने पंचांग वर्ष 1980 और 1981 के लिए भारत को क्रमशः 7.81 लाख मीट्रिक टन रा-वेल्यू और 7.29 लाख मीट्रिक टन रा-वेल्यू का वास्तविक कोटा आबंटित किया था।

(ख) सामान्यतया, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अन्तर्गत कोटे का पिछले तीन वर्षों में निर्यात के कार्य निष्पादन को ध्यान में रख कर विहित फार्मूले के अनुसार हिसाब लगाया जाता है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि पंचांग वर्ष 1980 और 1981 में चीनी का आयात करना पड़ा था और निर्यात के कोटे को पूरा नहीं किया जा सकता था, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन को एक जोरदार अभ्यावेदन

देना पड़ा था और उन्होंने भारत को बात-चीत के आधार पर वर्ष 1982 के लिए निर्यात हेतु 7 लाख मीट्रिक टन रा-वेल्यू का वास्तविक कोटा देना स्वीकार कर लिया है।

(ग) भारत सरकार की ओर से भारतीय राज्य व्यापार निगम ने अब तक कुल 4.67 लाख मीट्रिक टन की मात्रा का निर्यात करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय चीनी व्यापारियों के साथ ठेके किए हैं। आशा है कि इस समस्त आबंटित कोटे का 1982 के दौरान निर्यात कर दिया जाएगा और इसके मूल्य आदि के बारे में जहाज द्वारा चीनी भेजने के बाद ही जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

Unauthorised Occupation of DDA and MCD Land

4621. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the total acreage of land of DDA and Delhi Municipal Corporation under unauthorised occupation till May, 1982 ; and

(b) if so, the action being taken by Government to check such unauthorised occupation ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIAN SINGH) : (a) (i) D.D.A. 6250 acres approximately

(ii) M.C.D. 86 acres approximately

(b) The concerned organisations have intimated that action for removal of the encroachments is taken under the provisions of the public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971. The Delhi Development Authority has also reported that vacant lands are being fenced and watch and ward staff has been appointed to keep strict vigil over the land. A special Cell for checking illegal sale of acquired land has also been set up.

It has also been decided to bring forward legislation to amend the relevant laws to deal more effectively with unauthorised construction and encroachment of public land in Delhi.

Demand for change of allotted Agricultural Land not fit for Paddy

4622. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 129 persons from little Andaman were arrested for demanding change of their allotted agricultural land which is not fit for paddy cultivation ;

(b) whether it was assured by Chief Commissioner in Pradesh Council to get the land examined by Soil Expert from Delhi ; and

(c) if so, what action has been taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R.V. SWAMINATHAN): (a) to (c). The information is being collected from the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. It will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Unauthorised Construction of Footpath by Restaurant in I.N.A. Colony

4623. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state: